

**संपादकीय  
दबाव नहीं, कारोबार**

भारत और अमेरिका के व्यापार वार्ताकारों के बीच नई दिल्ली में चली दो दिन की बैठक शुक्रवार को बिना कोई बतीजा दिए खत्म हो गई। अब सबकी नज़रें वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अगले महीने प्रस्तावित अमेरिका यात्रा पर टिक गई है। उम्मीद जाताई जा रही है कि उनकी यात्रा के दौरान दोनों पक्षों में सहमति बना ली जाएगी, हालांकि उस प्रस्तावित यात्रा की तारीख भी अभी तय नहीं हुई है। प्रतिनिधियों की इस बैठक से उम्मीद इसलिए बड़ी हुई थी क्योंकि इसकी जमीन जापान में पिछले महीने जो-20 की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की मुलाकात में तैयार हुई थी।

तब ट्रंप ने यहां तक कह दिया था कि भारत के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेड डील होने वाली है। लेकिन उसके बाद हालात फिर से उलझने लगे और दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत शुरू होने से ठीक पहले ट्रंप ने देवीट कर कहा कि अमेरिकी सामानों पर भारत का ऊंचा शुल्क अब और मंजूर नहीं किया जा सकता। जाहिर है, बातचीत की नाकामी के पीछे अमेरिका का यही अंगिल रुख है। बातचीत जाता है कि अमेरिकी पक्ष चाहता था पहले भारत अमेरिकी सामानों पर शुल्क कम करे, उसके बाद बाकी मसलाओं पर बातचीत हो। लेकिन भारत ने शुल्कों में बढ़ावदारी अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों को विशेषाधिकार प्राप्त करने वालों की सूची से निकाल जाने के जवाब में की है। ऐसे में अमेरिकी कदम वापस लिए जाने से पहले भारत से शुल्क कम करने को कहना जायज कैसे हो सकता है? दरअसल इस गतिरोधी की जड़ें दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों के स्वरूप में हैं।

अभी दोनों देशों के बीच करीब 126 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार होता है जिसमें भारत का निर्यात 77.2 अरब डॉलर का है और आयात 48.8 अरब डॉलर का। इस लिहाज से अमेरिका के हिस्से सालाना 28.4 अरब डॉलर का व्यापार घटा है। लेकिन यह कागजी तस्वीर हकीकत से मेल नहीं खाती। असलियत यह है कि यह सिर्फ वस्तुओं के व्यापार का हिस्सा नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और फेसबुक जैसी अमेरिकी कंपनियों को और खासकर अमेरिकी बैंकों, बीमा कंपनियों और संस्थागत निवेशकों को भारत से होने वाली कमाई की नजर में रखें तो यह व्यापार घटा कहीं नहीं ठहरता। दिक्षित सिर्फ एक है कि अमेरिका को भारत से होने वाली यह बेहिसाब कमाई वहां रोजगार नहीं पैदा करती, और चुनावी राजनीति का तकाजा यह है कि रोजगार हर हाल में पैदा होते दिखने चाहिए।

सामानों के उत्पादन और व्यापार के बजाय वित्तीय कारोबार को तरजीह देने की नीति अमेरिकी शासकों ने लंबे समय से अपना रखी है, लेकिन ट्रंप सरकार उसका ठीकरा भारत और अन्य देशों पर फोड़ते हुए उनके हितों की कीमत पर अंतिरिक्त लाभ हासिल करने का नुगाइ बना रही है। लेकिन व्यापार हमेशा दोतरफा मामला होता है। यह किसी की छाती पर चढ़कर नहीं किया जा सकता, अमेरिकी निजाम जितनी जल्दी यह बात समझ ले, उतना अच्छा।



स्वर्ण, छ्वाज रजत और दो कांस्य पदक आए हैं। रस्स और नावें को दो स्वर्ण पदक मिले हैं। जबकि चीन, अस्ट्रिया, थाईलैंड और जर्मनी के दिस्से एक-एक स्वर्ण पदक आया। जूनियर पुरुष ट्रैप स्पर्धा में भोवनेश मेहंदीरता ने 116 का स्कोर किया लेकिन फाइनल में जाने से तीन अंक से चूक गए।

**निशानेबाजी में इलावेनिल ने 10 मीटर एयर राइफल में जीता स्वर्ण**

सुहल, जर्मनी, (आरएनएस)।

इलावेनिल वालारिवान ने सोमवार को जूनियर विश्व कप में हमवतन मेहुली धोप को 1.4 अंकों के अंतर से हरा स्वर्ण पदक अपने पास रखा है। इलावेनिल ने फाइनल में 251.6 का स्कोर किया। बालालीफिकेशन में सीधी परहेज हो गई। अपने पास रखने वाली मेहुली को दूसरे स्थान पर ही रोक दिया गया। फास की मारियाने मुलर के हिस्से कास्टर कप आया।

इलावेनिल और मेहुली ने श्रेया अग्रवाल के साथ 625.4 के स्कोर के साथ टीम स्पर्धा का स्वर्ण भी हासिल किया। इन तीनों ने मिलकर

# आरबीआई ने एसबीआई पर 7 करोड़ का जुर्माना लगाया

नईदिल्ली (आरएनएस)।

भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का उल्लंघन करने को लेकर देश के सबसे बड़े बैंक के 7 करोड़ का जुर्माना लगाया है।

रिजर्व बैंक के मुताबिक एसबीआई ने आय पहचान और संपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) नियमों का पालन नहीं किया। इसके अलावा बैंक ने चालू खातों को खोलने और उसके परिचालन के लिए जुर्माना एनपीए (नॉन-परफार्मिंगएसेट्स) और अन्य प्रावधानों से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया है। यह जुर्माना एनपीए (नॉन-परफार्मिंगएसेट्स) और अन्य जरूरी दस्तावेज देखने के बाबत लगाया गया है। इसी

तरह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगा है।

केंद्रीय बैंक के मुताबिक एसबीआई ने आय पहचान और संपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) नियमों का पालन नहीं किया। इसके अलावा बैंक ने चालू खातों को खोलने और उसके परिचालन के लिए जुर्माना एनपीए (नॉन-परफार्मिंगएसेट्स) और अन्य जरूरी दस्तावेज देखने के बाबत लगाया गया है। यह जुर्माना एनपीए (नॉन-परफार्मिंगएसेट्स) और अन्य जरूरी दस्तावेज देखने के बाबत लगाया गया है। इसी



से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने का बाबत लगाया गया है। बैंक से मिले जबाब और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद केंद्रीय बैंक के मुताबिक यह कार्रवाई नियमाकारी अनुपालन में खामियां पाई गई हैं। इन नियमों के बाबत लगाया गया है। आरबीआई द्वारा जांच रिपोर्ट और अन्य जरूरी दस्तावेज देखने के बाबत लगाया गया है। इसके अलावा भारतीय

रिजर्व बैंक ने साइबर सुरक्षा से जुड़े नियंत्रणों का पालन नहीं करने के आरोप में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि यह जुर्माना 9 जुलाई, 2019 को लगाया गया। केंद्रीय बैंक के मुताबिक यह कार्रवाई नियमाकारी अनुपालन में खामियां पाई गई हैं। इन नियमों के बाबत लगाया गया है। आरबीआई द्वारा जांच रिपोर्ट और अन्य जरूरी दस्तावेज देखने के बाबत लगाया गया है। इसके अलावा भारतीय

सबाल उठाना नहीं है। आरबीआई ने बताया कि 2016 में बैंक की स्लिप्ट प्रणाली से निकले 17.1 करोड़ डॉलर मूल्य के 7 खोयाधारी बातें संदेशों पर रिपोर्ट के बाद उसके साइबर सुरक्षा बातें का जांच में कई खामियां पाई गई हैं। इन नियमों के बाबत लगाया गया है। आरबीआई द्वारा जांच रिपोर्ट और अन्य जरूरी दस्तावेज देखने के बाबत लगाया गया है। इसके अलावा भारतीय

## पेट्रोल के दाम में वृद्धि पर लगा ब्रेक, डीजल के भाव भी स्थिर

नईदिल्ली (आरएनएस)।

पेट्रोल के भाव में पिछले तीन दिनों से जारी वृद्धि का सिलसिला



पूर्ववर्त क्रमशः 73.21 रुपये, 75.55 रुपये, 78.82 रुपये और 76.03 रुपये प्रति लीटर रहे। चारों में प्रति लीटर के दाम में बदलाव नहीं है।

डीजल के दाम में लगातार चौथे दिन स्थिरता बनी रही। उधर, अतरंगीश्वी बाजार में कर्वर्वत क्रमशः 66.24 रुपये, 68.31 रुपये और 69.43 रुपये और 69.96 रुपये प्रति लीटर बने रहे।

साल इसी महीने चांदी के आयात का मूल्य 36.42 करोड़ डॉलर था।

इस प्रकार चांदी का आयात इस साल जून में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 14.47 फीसदी बढ़ गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी के आयात में पिछले साल के मुकाबले 13.02 फीसदी की वृद्धि होने के बाद

चांदी की आयात का आयात इस साल जून में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 13.02 फीसदी की वृद्धि हुई।

वहीं, चींते महीने जून में 41.69 करोड़ डॉलर की चांदी का आयात किया गया जबकि पिछले साल जून में सोने-चांदी की मांग में सुस्ती बताई गई रही है।

आयात की आयात का आयात इस साल जून में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 13.02 फीसदी की वृद्धि हुई।

यह जबकि पिछले साल जून में सोने-चांदी की मांग में सुस्ती बताई गई रही है।

आयात की आयात का आयात इस साल जून में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 13.02 फीसदी की वृद्धि हुई।

यह जबकि पिछले साल जून में सोने-चांदी की मांग में सुस्ती बताई गई रही है।

आयात की आयात का आयात इस साल जून में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 13.02 फीसदी की वृद्धि हुई।

यह जबकि पिछले साल जून में सोने-चांदी की मांग में सुस्ती बताई गई रही है।